SHRI MENTAY PADMANABHAM; Just one point I would like to make, Madam. The point is that the Government of India has already declared that they are going to import 10 lakh bales of cotton into the country. Because of that announcement only this price of cotton has gone down by half. Therefore, the textile lobby is working overtime with the Ministry of Commerce and trying to manipulate the local prices, the indigenous prices to be paid to cotton growers or other growers. Therefore, what I demand through you, Madam, is that the Government of India should immediately announce that they are going to review the import policy on cotton in view of the situation developing in various parts of the country.

Thank you.

Need to Implement Sone River Project in Bihar

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, सोन नदी पर एक कदवन जलाशय परियोजना के लिए बिहार सरकार की ओर से बहुत पहले से प्रस्ताव आ रहा था। उसको 1989 में दिल्ली सरकार ने स्वीकार कर लिया और उस की नींव भी पड़ गई। कदवन जलाशया परियोजना का हश्र यह है कि नींव पड़ने के बाद उसमें एक खोभी मिट्टी नहीं पड़ी। न उस पर एक पैसा कहीं से आवंदित हुआ। बिहार सरकार की तो स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इस पर रुपया लगाये और भारत सरकार जो दे सकती है वह भी चाहती है कि बिहार को भूखों मारे। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि कदवन जलाशय परियोजना अगर नहीं बनी और बाणसागर डैम तैयार हो गया, जो तैयार होने वाला है एक दो साल के अंदर तो बिहार के 10 जिले जो बाउल आफ राइस कहे जाते थे जो अन्न भंडार कहे जाते थे वे मरूभूमि बन जायेंगे। बिहार के साथ जितना जुल्म हुआ है उसका एक नमूना रिहन्द डैम है। रिहन्द डैम से हमको एक मैगावाट बिजली नहीं मिली। तीन सौ की तीन सौ मैगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दे दी गयी। 18 हजार क्यूसेक्स पानी जो बिहार को मिलने वाला था वह भी अब नहीं मिलता हमें 9,5 या 6 हजार कभी-कभी मिलता है और हमारी फसलें मारी जा रही हैं। समझौते में था कि पानी तो मिलेगा 18 हजार क्यूसेक फीट बिहार को और बिजली मिलेगी 300 मेगावाट उत्तर प्रदेश को। लेकिन आज परिणाम यह है कि 300 की 300 मैगावाट बिजली जाती है उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से बिजली आ जाती है चंडीगढ़ दिल्ली लेकिन बिहार में नहीं जाती है। वह पानी जो 18 हजार क्यूसेक फीट था वह भी सिंगरौली के बिजली उत्पादन केन्द्र के लिए चला जाता है। हमारी फसलें मारी जा रही हैं। बाणसागर डैम से जो पानी आने वाला था अगर यह बन जाएगा, पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा तो मध्यप्रदेश पानी उधर रोक लेगा यहां हम भूखे मरने लगेंगे। भोजपुर, रोहतास, बंबुआ, बक्सर, औरंगाबाद, पटना, गया, नवादा ये जो जिले हैं ये सब के सब मरूभूमि बन जायेंगे। इनको मरूभूमि बनने से बचाने के लिए यह हुआ कि सोन नदी पर एक नया बांध लगाया जाए कदवन की जगह पलामू जिले में, फिर पानी को रोककर नया एक भंडार तैयार किया जाए। इस भंडार से साढ़े चार सौ मैगावाट पन बिजली और 27 हजार क्यूसेक फीट पानी तैयार हो सकता था यह बीच का रास्ता निकाला गया। दिल्ली सरकार अपनी जवाबदेही समझती नहीं है और बिहार को भूखों मारने पर उतारू है। ये दो बांध बाणसागर और रिहन्द बनने के बाद जो स्थिति हमारी बिगड़ी थी उसको सुधारने के लिए कदवन जलाशय परियोजना की परिकल्पना की गयी थी और उसको मंजूरी मिली थी। उस पर काम शुरू हो गया है लेकिन दिल्ली सरकार इसमें इतनी खामोश है। मैं आपको क्या बताऊं। अगर यह परियोजना पूरी नहीं हुई तो हमारे 9 जिले मरूभूमि हो जायेंगे। इनको कोई बचा ही नहीं सकता है। महोदया, मैं आपको एक और उदाहरण दूं। सोन नहर है एक। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी नहर, 110 साल पुरानी नहर है (समय की घंटी) जिस समय देश की किसी कोने

में नहरें नहीं थीं उस समय हमारे यहां नहरें बनायी गयी । इसलिए बनायी गयी कि 1857 में बगावत हो गयी । वह इलाका बागी था । इतना बागी था कि उसको कंट्रोल में लाने के लिए अंग्रेजों ने इसकी सिंचाई की व्यवस्था कराई, कि नहीं तो ये लोग बागी हो जाएंगे । इसलिए उस इलाके की सिंचाई करने के लिए अंग्रेजों ने यह बनायी । 110 वर्ष पुरानी नहर आज जर्जर अवस्था में है । 1680 करोड़ का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने कितनी बार पास किया कि इस सोन नहर का आधुनिकीकरण किया जाएगा लेकिन इसको एक पैसा नहीं दिया और वह कहती है कि पहले बिहार सरकार दे तब हम देंगे । बिहार सरकार के पास तो कुछ नहीं है । यहां का कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, मैंग्नीज, बाक्साइट, डोलोमाइट, कोरोमाइट आदि सारा का सारा वहां से लूट करके आप बाहर चले जाते हैं, क्वार्टज, यूरेनियम आदि सब लेकर चले जाते हैं । एक्साईज-ड्यूटी मार करके बाहर ले जाते हो । सारे का सारा फेट इक्वीलाइजेशन को लगातार सब स्टील ढो कर बम्बई पहुंचा दिया, पंजाब पहुंचा दिया, हरियाणा पहुंचा दिया ।

तो महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो दौलत लूट करके ले गये, तो हमको जीने लायक भी तो रहने दो । हमारे लिये पानी की भी तो व्यवस्था करो । हमारा कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा, सब लूट लिया, लेकिन कम से कम जीने लायक पानी की व्यवस्था करो, ताकि हम लोग जिंदा रहे और यह जिम्मेवारी दिली सरकार की है । बिहार सरकार के बस की बात नहीं है । इस साल अठारह सौ करोड़ रूपया बिहार सकार ने जो योजना का पैसा था, उसे लौटा दिया क्योंकि वह हम खर्च कर पाये । वह इसलिए कि जब हम बिहार का पैसा लागायेंगे तब वह दिल्ली वाला पैसा मिलेगा ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव आढाव (महाराष्ट्र): राम अवधेश जी, आप किस पर बोल रहे हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप इनको बोलने दीजिए । **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : कंदवन जलाशय परियोजना इसलिए समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार अपने हिस्से का पैसा देने में असमर्थ है । **(समय की घंटी)**

इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बाण सागर डैम और रिहंद सागर डैम से हमारी क्षति हुई है, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार पूरे तौर पर ले । कंदवन जलाशय परियोजना बनाने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार पूरे तौर से ले । **(समय की घंटी)** अगर नहीं लेगी तो बिहार के लोग भुखमरी ....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : इन घंटियों का कुछ मतलब है, राम अवधेश सिंह जी ।

श्री राम अवधेश सिंह : बिहार के लोग भूखमरी के शिकार हो जायेंगे और बिहार मरुभूमि बन जाएगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह दोनों विभाग इसमें काम करें-सिंचाई विभाग और पावर विभाग दोनों मिल करके इसमें काम करें ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): महोदया, मैं इसमें एसोसिएट करता हूं, पर उन्होंने जो लूट की बात कही उससे एसोसिएट नहीं करता । पर हां, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो बिहार सरकार को अपना हिस्सा उसमें लगाना है, कुछ कटौती करके-अब उसमें बिहार राज्य की अभी रिपोर्ट सबमिट हुई है कि बिहार राज्य इस देश का सब से गरीब राज्य है । खनिज पदार्थों में वह सब से अमीर है, किंतु आर्थिक रूप से वह सब से गरीब राज्य है, और इस वक्त नार्म्स को तोड़ कर बिहार राज्य की मदद करने की जरूरत है तथा इस जलाशय और

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

नहर परियोजना में जो पैसा बिहार को देना है, वह कटौती करके केन्द्र सरकार उसमें मदद करे, धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अब सदन की बैठक ग्यारह तारीख, सोमवार को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at forty-three minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 11th May, 1992.